



शौल

ई - पेपर

निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार



www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक - 50 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 19 - 26 दिसम्बर 2016 मूल्य पांच रुपए

क्या भाजपा अपने आरोप पत्र पर कारवाई के लिये शपथ पत्र के साथ लोकायुक्त या धरा 156(3) के तहत अदलत का रुख करेगी?

शिमला /बलदेव शर्मा

वीरभद्र सरकार के चार वर्ष पूरे होन पर जहां सरकार ने इस अवधि पर धर्मशाला में अपनी उपलब्धियों का व्योरा प्रदेश की जनता के सामने रखा है वही शिमला में भाजपा ने इन चार वर्षों में हार्टटाचार के एक आरोप पत्र के माध्यम से राज्यपाल के संज्ञान में बदला। इस पर जांच की मांग की है। सरकार का मुख्य व्यवस्था बनाये रखना है जनता के विकास के लिये काम करना, उनके जानमान की रक्षा करना और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सरकार का यह स्वीकृतिकारी व्यवस्था होता है। अपना दावित्य निभाकर सरकार लोगों पर कोई नेतृत्वान्वयी नहीं करता है। अपने दोनों ही सांपै द्वारा दोनों ही सांपै से एक सरकार द्वारा किये गये कार्यों को सरकार की उपलब्धियों कहना सही नहीं है। इसी तरह विषय का व्यवस्था रहता है कि सरकार के हर काम पर बारीक नजर रखे और किसी भी काम में कोई भ्रष्टाचार न होने दे। जहां भी



भ्रष्टाचार सामने आये उस पर कड़ी कारबाई सुनिश्चित करताये किसी भी सरकार और उसके विषय का आकलन इन्हीं मानकों पर होता है।

सरकार की उपलब्धियों कितनी सही मायनों में जीती पर है और कितनी केवल कामजूदी पर ही है इसकी प्रत्यक्ष जानकारी जनता को अपने आस - पास हुए विकास से मिल जायेगी। जनता को सरकार की योजनाओं का प्रयोग / अप्रयोग लाभ कितना मिला है इसकी भी उसे सीधी जानकारी मिल जाती है क्योंकि वही इनकी मुक्त भौमि होती है। लेकिन इस सबको अमलीकृत करने हुए किस स्तर पर कितना ध्यान - घोटाला हुआ है इसकी उसे कोई सीधी जानकारी नहीं होती है। इसके लिये वह मोडिया और विषय पर निर्भर करता है क्योंकि इन्हीं दो से यह अपेक्षा रहती है कि वह सरकार के कामकाज पर नजर रखते हुए उसे भ्रष्टाचार करने से रोके और उसकी जानकारी जनता के सामने रखे।

प्रदेश भाजपा ने वीरभद्र सरकार

के स्विलाफ आरोप पत्र राज्यपाल को सौंप कर अपनी जिम्मेदारी का पक्ष निभाया है। सरकार में फैले भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में लाकर रख दिया है। लेकिन व्या भाजपा की बतार विषय जिम्मेदारी इसी से पूरी हो जाती है। सरकार के चार वर्षों के आरोप पत्र के माध्यम से राज्यपाल के संज्ञान में बदला। इस पर जांच की मांग की है। सरकार का मुख्य व्यवस्था बनाये रखना होता है जनता के विकास के लिये काम करना, उनके जानमान की रक्षा करना और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सरकार का यह स्वीकृतिकारी व्यवस्था होता है। अपना दावित्य निभाकर सरकार लोगों पर कोई नेतृत्वान्वयी नहीं करता है। अपने दोनों ही सांपै से एक सरकार द्वारा किये गये कार्यों को सरकार

आरोप है। राजभवन के पास ऐसे समझे की जांच के लिये अपना कोई स्वतन्त्र नहीं होता और सरकार तथा उसकी विजिलेन्स इन पर कोई धमकी भी दी है। मुख्यमन्त्री की धमकी के परिदृश्य में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि भाजपा की आरोप रिपोर्ट बनाकर इन पर कारबाई करने के लिये अधिकृत है। जो आरोप पत्र के साथ अपना एक शपथ पत्र लगाकर इसे प्रदेश के लोकायुक्त को सौंपे।

लोकायुक्त के अतिरिक्त दूसरा कवित्य इन आरोपों पर धरा 156(3) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाकर इन पर सिंधे एफआईआर दर्ज करवाने का रस्ता अपनाये। यदि ऐसा नहीं होता है तो स्पष्ट हो जायेगा कि भाजपा भ्रष्टाचार के स्विलाफ कर्तव्य गंभीर नहीं है। बतिक इसके माध्यम से जनता के लिये अधिकृत है। उसमें बहुत सीधी आरोप है।

शांडिल और कर्ण सिंह को छोड़ वीरभद्र का पूरा मन्त्रीमण्डल गंभीर आरोपों के साथ में

- ✓ कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 40 नेताओं पर आरोप
- ✓ मुख्यमन्त्री की पत्नी, बेटा प्रधान निजि सविच और सुरक्षा अधिकारी भी आरोपों में
- ✓ क्या वीरभद्र आरोप पत्र के मन्त्री के स्विलाफ मानहानि का दावा दायर करेंगे

शिमला /बलदेव शर्मा

भाजपा ने जब वीरभद्र सरकार के स्विलाफ आरोप पत्र लाने की घोषणा की थी तभी से मुख्यमन्त्री बरबार यह कहते आये हैं कि वह छठे बिना प्रमाणों के आरोप लगाने वालों के स्विलाफ कारबाई करेंगे, मानहानि का

एवम कथि भंगी सुजान सिंह पठानिया, वन मन्त्री ठाकुर सिंह भर्मारी, उद्योग मन्त्री मुकेश अमिनहोस्ती, शहरी विकास एवम आवास मंत्री सुधीर शर्मा, आवकारी एवम करायान मंत्री प्रकाश चौधरी, पंचायती राज एवम ग्रामीण विकास मन्त्री अनिल शर्मा और विधानसभा उपाध्यक्ष

सिपाहिया, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिंह पठानिया, राम लाल ठाकुर, रव्या जातीलुला, केवल सिंह पठानिया, सुभाष भगतेट, राजेन्द्र राणा, चन्द्र कुमार, राकेश कालिया, बन्धु ठाकुर और चेत्राम सब आरोपों के साथ में हैं। लेबर वैल्फरेय बोर्ड, प्रदेश के तीनों

विश्वविद्यालय, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर और प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा विधान सभा सचिवालय तक आरोपों में हैं। आरोपों के साथ पुष्ट करने वाले प्रमाण भी साथ सौंपे गये हैं। आरोपों की इतनी लम्बी सूची पूरे तन्त्र सेवा आयोगों के द्वारा देखने से यह सावधान अहम है। इनकी पत्नी प्रतिभा

सिंह, बेटे विकासादिव्य सिंह, प्रधान निजि सविच सुभाष आहलवानिया और मुख्य मन्त्री के सुरक्षा अधिकारी पदम ठाकुर के स्विलाफ गभर आरोप है। मुख्यमन्त्री परिवर्त के अतिरिक्त सिंह इन्द्रदत्त लवनपाल, नीरज भरती और सचिवालय को सचिवालय को भेज दिये जाते हैं और आरोप पत्र सौंपने वाले व्यापारों होकर अपनी राजनीति में व्यस्त हो

जगत सिंह नेगी के स्विलाफ गंभीर आरोप हैं। मन्त्रीयों के अतिरिक्त, कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्तु, सीपीएस ठाकुर के देखने से यह सावधान प्रमाण भी हानि पहुंचाई गयी है और जब यह हानि पहुंच रोहित ठाकुर पर भी आरोप है। इनके अतिरिक्त हर्ष महाजन, जगदीश

चिंह लग जाता है। क्योंकि जब विभाग के मन्त्री पर आरोप लगाते हैं तब उस विभाग से जुड़ा शीर्ष प्रशासन भी त्वत् ही आरोपों के घेरे में आ जाता है। इन आरोपों को देखने से लगता है प्रोफेशनल को सैकड़ों करोड़ के राजस्व की हानि पहुंचाई गयी है और जब यह हानि पहुंच शेष पूछ 7 पर...



बुद्धिमान व्यक्ति भी तब घोर परेशानी से पिर जाता है, जब वह किसी मूर्ख व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करता है कि सही कथा है और गलत कथा है।

त्रैसम्पादकीय

पुराने नोट जमा करवाने की सुविधा से किसे लाम पिल रहा है



आठ नवम्बर को रात आठ बजे प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की कि आज रात बारह बजे के बाद पांच सौ और एक हजार के नोट लीगल टैंडर नहीं रहेंगे। यह केवल कागज के टुकड़े रह जायेंगे। इन नोटों के स्थान पर पांच सौ और दो हजार के नये नोट जारी किये गये हैं। प्रधान मन्त्री ने इस फैसले को कालाधन और उसके धारकों के खिलाफ बड़ा कदम बताते हुए आम को भरोसा दिलाया था कि इस फैसले से जो व्यवस्थित परेशानीं सामने आयेंगी वह पचास दिन में समाप्त हो जायेंगी। मोदी ने देश से पचास दिन का बिना शर्त सहयोग मांगा था और देश ने यह सहयोग उन्हें दिया है। प्रधान मन्त्री ने यह भी दावा किया गया कि इससे मंहगाई कम होगी। आठ नवम्बर को यह घोषित नहीं किया गया कि पुराने नोट कितने समय तक कहां उपयोग में रहेंगे। इसके लिये समय – समय पर नियमों में सशोधन होता रहा और पुराने नोटों के उपयोग की सहृदैयत मिलती रही। इसी में कालेधन के धारकों को भी यह सुविधा दी गयी कि वह भी अपना धन घोषित कर सकते हैं उनके खिलाफ कोई कारबाई नहीं की जायेगी उनसे कुछ पूछा नहीं जायेगा। केवल उनके लिये टैक्स आदि की मात्रा बढ़ा दी गयी। इस सब में जो फैसला नहीं बदला वह यही कि पुराने नोटों का चलन बाजार के लिये बन्द हो गया। अब पुराने नोट के बदल रिजर्व बैंक की धरोहर रह जायेगा। पुराने नोटों को जमा करवाने की समय सीमा में जो बढ़ान्तरी होती रही है उसके लिये यह तर्क आता रहा है कि रिजर्व बैंक ने पांच सौ और हजार के जिनने नोट प्रिंट किये थे वह सारे वापिस नहीं आये हैं। ऐसे में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि जब पुराने नोटों की वैधता ही आठ नवम्बर से समाप्त हो गयी है तब रिजर्व बैंक इन्हे अपने पास लेकर क्या करेगा।

नोटबद्दी कालाधन समाप्त करने के लिये लायी गयी। कालाधन वह धन होता है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि आयकर डिजिने का प्रयास ही कालेधन का जनक बन जाता है। अन्यथा हर खरीद – फोरेस्ट पर हम प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष रूप से 56 करों की अदायगी करते हैं। यह कर उन पर भी बराबर लागू रहते हैं जिनकी आय आयकर के दायरे में नहीं आ पाती है। इस समय भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तीन प्रतिशत लोग आयकर देते हैं। 92 प्रतिशत वह लोग हैं जिनकी आय ही दस हजार या इससे कम है। इनके पास आयकर से छिपाने के लिये ही ही कुछ नहीं। इस तरह केवल पांच प्रतिशत लोग बच जाते हैं जो आयकर की चोरी करके कालाधन अर्जित कर रहे हैं। इन पांच प्रतिशत कालाधन धारकों के खिलाफ कारबाई के लिये नोटबद्दी लायी गई। यहां यह भी विचारणीय है कि करंसी के मुद्रण, नियमन और सचालन की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक एक स्वातंत्र्य है। उसका हर फैसला उसके निवेशक मण्डल में पूरी तरह गहन विचार के साथ लिया जाता है और तब उस फैसले से सरकार को सूचित किया जाता है। करंसी के मुद्रण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उतनी ही करंसी प्रिंट की जायेगी जिनमा ही आपके पास गोल्ड का धातु है इसलिये विश्व भर में गोल्ड ही इसका मानक बन चुका है। इसका अर्थ है कि गोल्ड के सुक्षित भण्डार के अनुभाव में ही करंसी का मुद्रण होता है।

अब जब नोटबद्दी की गयी तब यह आंकड़े सामने आये की पांच सौ और हजार के नोट कुल करंसी के 86% हैं। अब जब 86% करंसी का चलन वैध नहीं रहा तब यह पुराना किसी के घर तिजोरी में बन्द रहे हो यह रिजर्व बैंक के पास रहे उसकी कीमत तो एक कागज के टुकड़े से अधिक नहीं है। फिर 86% करंसी का अनुपातित गोल्ड रिजर्व तो सुरक्षित पड़ा ही है। इसमें नुकसान तो केवल छाई औं कागज की कीमत का ही है। कालाधन और बैंकों संपत्ति की घोषणा की समय सीमा 30 सितम्बर को समाप्त हो गयी थी। अब नोटबद्दी में आम आदीओं को जो 92% के आंकड़े में आता है उसको पुराने नोट बदलने के लिये काफी समय लिया गया है। अब इस समय इन कालाधन धारकों को पुराने नोट जमा करवाने की सुविधा व्यापों दी जा रही है। इससे उनका नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्या यह सुविधा देने के बालंधार के खिलाफ कारबाई के सारे दायों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब जब छापों में नये नोट फिर से इन कालाधन धारकों के पास मिल रहे हैं तो उससे भी यही प्रश्नांगत होता है कि इन लोगों पर इस फैसले का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें यह यह पुराने नोटों को बदलने के लिये एक तय सीमा के बाद छूट न दी जारी और बिजली, पानी टैलिफोन आदि सारी सेवाओं के बिलों के भुगतान में यह सुविधा देने की बजाये इन बिलों का भुगतान ही पाचस दिन किश्तों में लिया जाता तो उसके परिणाम कुछ और ही होते। अब पुराने नोटों को जमा करवाने के समय को बढ़ाने से नोटबद्दी का पूरा फैसला सचालों के धोंगे में खड़ा हो जाता है।

हिमाचलःआपकी फिल्म का अगला पड़व

हिमाचल की पर्वतीय मालाओं में बसा हिमाचल प्रदेश अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, शीत जलवायु, हरी-भरी घाटियों और आतिथ्य सत्कार प्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की अपार सौंदर्यता विश्व के विभिन्न भागों के फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में शूटिंग के लिए आकर्षित करती है। इसका श्रेय यहां के सुन्दर पर्वतीय शहरों, आश्रयों, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण व स्कीईंग जैसी अन्य गतिविधियों को जाता है। हिमाचल में शिमला, मण्डी, धर्मशाला, रोहतांग, नगर आदि कई मनमोहक स्थल हैं।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न फिल्मों की शूटिंग की गई है जैसे अनंत वा, बद्रीनाथ, बैंग बैंग, ब्लैक, देव डी, अन्धीरन, हाइवे, लव वी टैट, लायर्स डाईस, लुटेरा, लव इन शिमला, राज़: द मिस्ट्री कन्टीन्यूस, रानी पदमीनी, रोजा, शिप ऑफ थिसिंयस, यंग मलगा।

से नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। राज्य के अनंत वा, बद्रीनाथ, बैंग बैंग, ब्लैक, देव डी, अन्धीरन, हाइवे, लव वी टैट, लायर्स डाईस, लुटेरा, लव इन शिमला, राज़: द मिस्ट्री कन्टीन्यूस, रानी पदमीनी, रोजा, शिप ऑफ थिसिंयस, यंग मलगा।

फिल्मांकित पल जो हमारी फिल्मी धरोहर में बढ़ाती है, को अर्जित व संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करेगी। राज्य भविष्य में सभी उपलब्ध फिल्मी सामग्री की सूची अतिरिक्त राज्य सरकार फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने के नजरिये से फिल्म स्टूडियो की

राज्य सरकार

शिमला, कुल्लू व धर्मशाला में स्थित हवाई पटिकाओं के विस्तार व स्तरोन्नयन पर भी विचार कर रही है ताकि यहां नियमित उड़ानों का सचालन हो सके। इसी फिल्मों के निर्माण में अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी तथा राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर फिल्म निर्माता सरकारी आवास, परिवहन व उपकरण जैसी सुविधाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो उहें अतिरिक्त सुविधाएं व छूट भी प्रदान की जा सकती है।

फिल्म निर्माता राज्य के सौंदर्य से बेहद प्रभावित हैं तथा उन्हें आशयर्थी होता है कि भारतीय लोग भवानी ही करंसी प्रिंट की जायेगी जिनमा ही आपके पास गोल्ड का धातु है इसलिये विश्व भर में गोल्ड ही इसका मानक बन चुका है। इसका अर्थ है कि गोल्ड के सुक्षित भण्डार के अनुभाव में ही करंसी का मुद्रण होता है।

राज्य सरकार भी प्रदेश में निर्माताओं की ग्रूटिंग में धातु के माध्यम से फिल्म पर्यटन करने में सक्रिय भूमिका

स्थानाना को सभावनाओं को भी जांच होती है।

स्वस्थ मनोरंजन के स्रोत के अतिरिक्त, सिनेमा आय व रोजगार सृजनाता की अपार संभावनाएं भी प्रदान करता है। इसके में देनेनजर प्रदेश में सिनेमाघरों की स्थानाना व प्रोत्साहन करने में सक्रियता है। इसमें निर्माताओं की सहायता के साथ विचारणा के लिए एक सिंगल चिंडी क्लीयरेंस प्रणाली स्थापित करने के लिए ग्रूटिंग की अनुभावित, भवनों को सरल किया गया है। प्रशासन द्वारा शूटिंग को अनुमति देना चाहता है।

स्वस्थ मनोरंजन के अनुभावित करने के लिए प्रक्रियाओं व अनुभावितों को सरल किया गया है। प्रशासन द्वारा शूटिंग को नुकसान से बचाने के लिए बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

राज्य की फिल्मी गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन के लिए अलावा राजस्व भी अर्जित होगा। इसके अतिरिक्त दूरगामी व अल्प - विकसित क्षेत्रों में रोजगार भी सृजित होगा। प्रदेश के युवा व ग्रामीणों में फिल्मी भौमिका को प्रोत्साहित करने के लिए इश्य से फिल्म महात्मवंशों व अन्य फिल्म सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

राज्य को फिल्मी गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन के लिए अलावा राजस्व भी अर्जित होगा। इसके अतिरिक्त दूरगामी व अल्प - विकसित क्षेत्रों में रोजगार भी सृजित होगा। प्रदेश के युवा व ग्रामीणों में फिल्मी भौमिका को प्रोत्साहित करने के लिए अभियानी है। मण्डी जिला जहां प्रदेश का एकमात्र अभिनय संस्थान है, कलाकारों व अभिनयकारों की राजधानी कहलाता है।

देव की समृद्ध फिल्मी धरोहर के संरक्षण व भावी यौवाणों के लिए इन्हें उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय फिल्म धरोहर अभियान आरम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य फिल्मों के लघु फिल्मों का डिजिटलकरण करना है। राज्य सरकार एतिहासिक फुटेज, राजसी व राजनीतिक परिवारों द्वारा संरक्षित वृत्तचित्र तथा इसके अन्य

वर्षांत लोगों के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन व सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य

पति के देहांत के बाद न पत्नी को पैशन न ही बटे को रोजगार

शिमला /शैल। पति की पैशन को हो गया था। तब से लेकर उनकी या कल्याणमूलक आधार पर वे इसके लिए जाए और उनकी मिल जाए और उनकी भेजा गया पत्र

विभाग के निदेशक की ओर से नौकरी देने के लिए मंजूर सरकार को भेजा गया पत्र

अपनी फरियाद लेकर स्वर्गीय राम लाल की पत्नि अपने बेटे गुलशन कुमार के साथ तपोवन में विधानसभा के दोरान मंत्री सुजानसिंह व मुख्यमंत्री वीरभद्र शह से मिलने पहचानी। गुलशन कुमार ने बताया कि

उनके पिता का देहांत 5 नवंबर 2015

मां को न तो कोई पैशन मिली है और मे कार्यरत थे।

शिमला /शैल। राजकीय पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के कार्य में जुट महाविद्यालय शाहुर के छात्रों ने जम गए हैं। इस जश्न का आयोजन कैंपस में

और राजनीतिक हितों को साधना है चाहे इसके लिए छात्रों का यही जश्न अथूरा न रहे। इसके लिए भी छात्रों ने खाल संज्ञान भी किया हुआ था। लड़कों ने जाम तो छलकाए ही, साथ में खूब ठुमके लगाए और हूटिंग भी की। लेकिन इसकी रुबर न तो पुलिस की लोगी और न को कॉलेज प्रशासन को। कॉलेज के प्राचार्य कुलदीप कुमार बांटा ने कहा कि उन्होंने छात्रों पर नजर रखने के लिए चौकीदार को लगाया हुआ था और उन्हें छात्रों के द्वारा जाम छलकाने की कोई खबर नहीं मिली। इस जश्न के लिए NSU की इकाई ने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति ली हुई थी। इस न्यू इयर पार्टी में NSU के प्रवेश सचिव सोनू भारद्वाज, जिता महासचिव सुनील यश्याल, और कैप्स दिन था क्योंकि शिक्षक आज से उत्तर



NSU की इकाई ने करवाया था। वाले छात्र परिषाके के बोडे से 2 दिसंबर को फी हुए थे और साथ में नए साल का राजनीतिक धड़ों ने जिता सत्याओं में स्वागत एवं संतान में करना चाहा। यही नहीं, महाविद्यालय में इस सत्र का ये अविरो इकाइयों का गठन किया हुआ है। इनका मकसद अपने आकाऊओं को खुश करना

टांडा में आंखों के आपरेशन के बाद चली गई रोशनी, तीन सदस्य समिति करेगी जांच

शिमला /शैल। टांडा डेविल कालेज में आंखें के आपरेशनों के बाद विजन चले जाने के मामले में सरकार ने तीन सदस्य समिति से जांच कराने का एलान किया है। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर की जारीगी। स्वास्थ्य भंडी कौल सिंह ठाकुर ने तपोवन में सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा इसके लिए इविरा गांधी डेविल कालेज के आई विभाग के प्रमुख व वाकी दो फ्रैकेसरों को जाच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बर्खास्त आईआर दर्ज कर दी जाएगी।

टांडा अस्पताल में 12 तरीकों

संजीवन लाल, स्थानीय लाल, त्रिलोक, बाकियों को मारंटा के रोटेरी अस्पताल

इशा कुमारी व गीता के आपरेशन के लिए वे थे। आपरेशन के पहले आंखों को साफ करने के

लिए ट्राइपीन नामक दवा आंखें में डाली गई।

इसके बाद आपरेशन किए गए जिनमें से चार रोगियों को घर भेज दिया गया है। जबकि एक रोगी अस्पताल में रहा। इन रोगियों की आंखों में संक्रमण हो गया जिसकी वहज से दो मरीजों को पीजीआई भेज दिया गया व

हुआ है कि इनका सबका विजन चला गया है या नहीं। रोगियों जो भी सकती हैं और नहीं भी।

सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और मार्किट से जो दवा इनकी अंतर्वें में डाली गई उसे वापस भग्ना लिया गया है। चौंके देव निजी कोमिसिट से ली गई थी अगर दवा निर्माणकर्ता के लाई से संक्रमित हो तो उसके विवाकार एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी।



अनुराग ठाकुर ने युवा मर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व पूनम महाजन को सौंपा

शिमला /शैल। भारतीय जनता प्रकाशनी के ही गई। नर्तजतन परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है।

गुलशन ने कहा कि वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व कृष्ण मंत्री सुजानसिंह पठानिया से कई बार भिन्न चुके हैं। लेकिन दोनों की ओर से अब तक केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं न पैशन लगी और उनकी कर्मसूलक आधार पर नौकरी ही मिली। आज भी हम अपनी फरियाद लेकर आए हैं। अपनी दास्तां सुनाते हुए गुलशन की मां की आंखों से आसू छलक आएं। उन्होंने कहा की सरकार उनकी समस्या का हल नहीं कर पाया है। गौरतलब हो कि स्व. रामलाल कृष्ण विधायक के मृदा संरक्षण विधि में नूरपूर्ण



इस पद की जिम्मेदारी सांसद पूनम महाजन को सौंपी है।

इस भौके पर अपने भाषण में अनुराग ठाकुर ने अपने कार्यकाल में उल्लेख कर, एक उज्ज्वल युवा मर्वा नए अध्यक्ष को सौंपा है। अनुराग ठाकुर ने कहा की, सेवा संघर्ष और बलिदान, युवा मर्वा की प्रवर्तन का नाम उन्होंने दिया और और इसी नाम को आगे रखवाएं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि, पूनम महाजन इस अभियान को आगे बढ़ाएगी।

पूनम महाजन ने कहा कि, उन्हें अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पंचकालियों द्वारा योजना के माध्यम से सरकार के कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचायी और हाल ही में डिजिटल पैसा अभियान की शुरूआत कर, प्रायोगिक जी के लेस कैसे सोसाइटी के संकल्प को आगे बढ़ाया। अनुराग ठाकुर ने आशा व्यक्त कि, पूनम महाजन इस अभियान को आगे बढ़ाएगी।

पूनम महाजन ने कहा कि, उन्हें अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जानकारी घर घर तक पहुंचायी का राष्ट्रीय उपायक्ष के रूप में काम करने मिला और आगे भी वे अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जो युवा मर्वा ने सफल काम किया है उसको आगे बढ़ाएगी।

कांगड़ा में बसों की छाँतों पर सफर

शिमला /शैल। द्रमण से सिंहता और चंबा की ओर जाने वाली निजी बसें सवारियों की जान की जिस्मिन में डाल रही हैं। इस रूट पर चलने वाली निजी बसें ज्यादा से ज्यादा सवारियों को ढोने के चकवाले तुरन्त बस पर यात्रा करवाए रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कांगड़ा से भिटायत विधानसभा क्षेत्र के चाहने के लिए बस ठहरावों पर नहीं रुकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि सरकारी बस और निजी बस स्टाफ के बीच अच्छा दोस्ताना है। नरीजतन लोगों को निजी बसों की छाँतों पर जेसिम उठा कर सफर करना पड़ता है।

जब आरटीओ कांगड़ा संजय कुमार धीमान से जब इस बारे में दृभाष पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह आजकल छुट्टी पर है। साथ ही जब उन्हें पूछा

पाता है।

गौरतलब हो कि कांगड़ा परिवहन मंत्री जी एस बाली का अपना जिला है। बसों में एक सीमा से ज्यादा यात्रियों को नहीं बिठाया जा सकता। इस बावत प्रदेश हाइकोर्ट के आदेश भी हैं। लेकिन मंत्री बाली के अपने जिले में इन आदेशों को उलटा टांग दिया गया है।

द्रमण स्थित चौक पर दुकानदारों का कहना है कि यहां से चंबा और सिंहता की ओर जाने वाली लगभग सभी बसों की स्थिति ऐसी ही रहती है। ज्यादा देव रोगियों को बसों में टूटने की कठिनता है और उन्होंने कहा कि यहां रोगी को घटना सामने लाया जाएगा। विभाग व पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं।

